



7 February, 2024

केंद्र ने 'भारत' चावल की बिक्री आरम्भ की

संदर्भ: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में 'भारत' नाम से चावल जारी करने की पहल की है तथा इसके वितरण के लिए 100 मोबाइल वैन का उद्घाटन किया।

➤ किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता:

- 'भारत' चावल के अलावा, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर भारत आटा, भारत दाल, प्याज, चीनी और तेल जैसी अन्य प्रमुख वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी।
- इन आवश्यक वस्तुओं को केंद्रीय भंडार, NAFED और NCCF जैसे आउटलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे किफायती दरों पर व्यापक उपभोक्ता आधार तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होती है।

➤ उपभोक्ता कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता:

- प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, समाज के सभी वर्गों के सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की बारीकी से निगरानी और विनियमन करके, उपभोक्ता कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- ये पहल उचित मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से किसानों का आय समर्थन करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

➤ खाद्य क्षेत्र में कीमत नियंत्रण के प्रयास:

- 'भारत' चावल का खुदरा रूप में विक्रय के लिए उपलब्ध होना; आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने और आपूर्ति में वृद्धि के साथ-साथ नियंत्रित मूल्य निर्धारण के माध्यम से बाजार को स्थिर करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- यह पहल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को किफायती बनाए रखने, समग्र खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के पिछले प्रयासों पर आधारित है।

➤ 'भारत' चावल खुदरा लॉन्च विवरण:

- 'भारत' चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग के उपभोक्ता-अनुकूल पैकेजिंग आकार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 29₹/किग्रा है, जो इसे विभिन्न आकार और बजट वाले घरों के लिए सुलभ बनाता है।
- यह चावल आरम्भ में केवल निर्दिष्ट दुकानों पर ही उपलब्ध होगा। हालांकि व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुंचने के लिए अन्य खुदरा प्लेटफार्मों और ई-कॉमर्स चैनलों में इसके विस्तार की योजना है।

➤ उपलब्धता और उपभोक्ता पहुंच का विस्तार:

- सरकार का लक्ष्य विभिन्न खुदरा चैनलों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'भारत' चावल की उपलब्धता को निर्दिष्ट दुकानों से आगे बढ़ाना है।
- यह विस्तार देश के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा बुनियादी आवश्यकताओं तक समावेशिता और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

➤ उपभोक्ता कल्याण और किसान सहायता के लिए सरकारी प्रयास:

- सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पीएमजीकेवाई जैसी पहल लागू करती है, जबकि किसानों को उनकी उपज हेतु एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य सुनिश्चित करके आय समर्थन करती है।
- इन उपर्युक्त उपायों के माध्यम से, सरकार एक स्थायी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए, उपभोक्ता सामर्थ्य और किसान आजीविका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है।

➤ आवश्यक वस्तु कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास:

- खुदरा पहल के अलावा, सरकार कीमतों को स्थिर करने तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खरीद कार्य करती है और पीएमजीकेवाई का लाभ देती है।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के ये प्रयास अति आवश्यक हैं, खासकर आर्थिक अनिश्चितता या वैश्विक कमोडिटी बाजारों में उतार-चढ़ाव के समय।

➤ खाद्य तेल बाजार में कीमत नियंत्रण के उपाय:

- सरकार घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क को समायोजित करने और अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझानों की बारीकी से निगरानी करने जैसे उपायों को लागू करती है।
- यह सुनिश्चित करके कि वैश्विक कीमतों में बदलाव घरेलू बाजारों को प्रभावित कर सकती है, सरकार का लक्ष्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बनाए रखना है।

➤ बाजार स्थिरता में कीमत स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की भूमिका:

- मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) मूल्य अस्थिरता को कम करने और कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के माध्यम से, बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से, पीएसएफ का लक्ष्य आवश्यक वस्तुओं की स्थिर कीमतों और उपलब्धता को बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं और किसानों दोनों की रक्षा करना है, जिससे आर्थिक लचीलापन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

संदर्भ: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के.एम. शोभा करंदालाजे ने भारत में एफपीआई की वृद्धि एवं उसके कारणों का उल्लेख किया।

➤ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास:

- वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण (एफपी) उद्योग भारत की जीडीपी, रोजगार और निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वर्ष 2021-22 तक पिछले सात वर्षों में, एफपी क्षेत्र ने लगभग 7.26% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) को प्रदर्शित किया है।
- एफपी क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वर्ष 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.08 लाख करोड़ हो गया है।

➤ सरकारी पहल और योजनाएँ:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), आधुनिक बुनियादी ढांचे और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विकसित करने के लिए, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) जैसी योजनाएं संचालित करता है।
- साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्थापित करने या उनके उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।
- इस संदर्भ में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर खाद्य अग्रणी देश बनाना और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों की मांग को बढ़ाना है।

➤ निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास:

- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से छूट प्राप्त है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों खाद्य उत्पादों पर कम जीएसटी दरें लागू होती हैं, जो 71.7% से अधिक खाद्य उत्पादों को कवर करती हैं।

➤ असंगठित क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख अप्रजिकृत और अनौपचारिक उद्यम शामिल हैं।
- इन सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों को ऋण, प्रौद्योगिकी, ब्रांडिंग, विपणन और खाद्य सुरक्षा उपायों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

➤ आत्मनिर्भर भारत पहल:

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना का उद्देश्य वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करना है।

Face to Face Centres

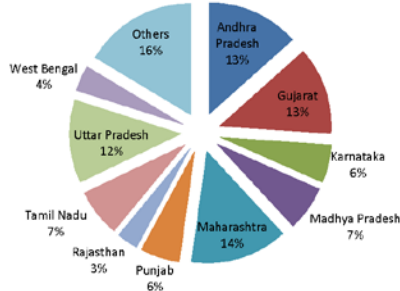




7 February, 2024

- इसके दिशा में सभी 36 भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित इस योजना ने ऋण मंजूरी, प्रारंभिक पूंजी जारी करने और लाभार्थियों के प्रशिक्षण में व्यापक प्रगति दर्शाई है।

Share of different states in Organised food processing units



प्रमुख विकासवात्मक आंकड़े:

- क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए 72,556 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें ओडिशा में स्वीकृत 1175 ऋण भी शामिल हैं।
- 236,704 एसएचजी सदस्यों के लिए आधार पूंजी के रूप में 771.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें ओडिशा में 23,400 एसएचजी सदस्यों के लिए 67.91 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 62,140 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें ओडिशा के 6439 प्रशिक्षित शामिल हैं।
- अब तक 14 ओडीओपी ब्रांड और 166 उत्पाद सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा चुके हैं, इस संबंध में ओडिशा राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

2024 के लिए जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि

संदर्भ: हालिया प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 95% प्राकृतिक आपदाओं के लिए मौसम संबंधी आपदाएँ जिम्मेदार थीं, जिसके परिणामस्वरूप 1 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

2023 में वैश्विक प्राकृतिक आपदा रुझान:

- वर्ष 2023 में, पूरे विश्व में कुल 398 प्राकृतिक आपदाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 380 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- यह वर्ष 2022 में दर्ज किए गए अनुमानित \$355 बिलियन के आर्थिक नुकसान से अधिक वृद्धि दर्शाता है।
- इस वर्ष 66 अरब डॉलर की आर्थिक हानि की घटनाएँ और 37 अरब डॉलर की बीमित हानि की घटनाएँ भी देखी गईं।
- इन सभी में से 95% प्राकृतिक आपदाओं के लिए केवल मौसम संबंधी कारक जिम्मेदार थे, जिससे कम से कम 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- एओन पीएलसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी जलवायु और आपदा अंतर्दृष्टि रिपोर्ट, 21वीं सदी की तुलना में नुकसान संबंधी 22% की वृद्धि दर्शाती है।

- यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूकंप और गंभीर संवहनी तूफान (एससीएस) इस वृद्धि के महत्वपूर्ण चालक थे।
- बीमा कवरेज में केवल \$118 बिलियन का भुगतान किया गया, जो 69% की सुरक्षा अंतर को दर्शाता है। यह वर्ष 2022 में दर्ज 58% की सुरक्षा भुगतान से अधिक है।

वैश्विक सुरक्षा अंतर:

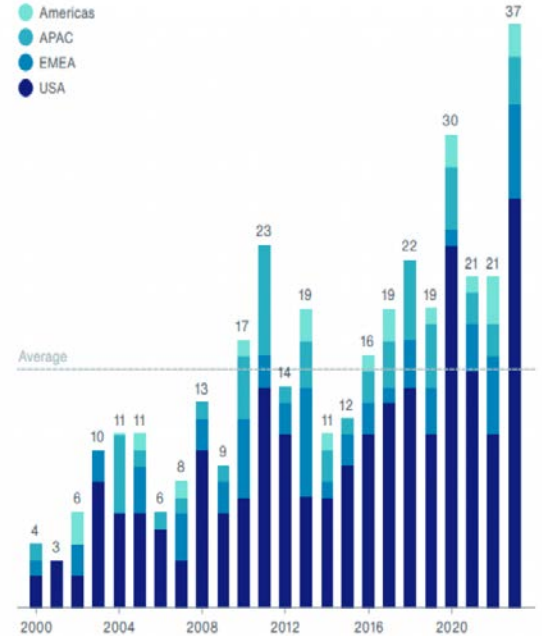
- बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, वर्ष 2023 में बीमा कवरेज अंतर बढ़ गया था।
- सबसे व्यापक सुरक्षा अंतर एशिया और प्रशांत क्षेत्र (91%) में मौजूद था, इसके बाद अमेरिका (गैर-यूएस) (87%) और यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका (83%) का स्थान था।

विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव:

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 64% से अधिक नुकसान बाढ़ के कारण हुआ, जहां बीमा की पहुंच या कवरेज अपेक्षाकृत कम है।
- भारत में, मौसमी बाढ़ के कारण लगभग \$300 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ और वर्ष 2023 में 2,600 से अधिक लोगों की जान-हानि हुई।
- अमेरिका में, बीमा ने लगभग \$80 बिलियन की आर्थिक क्षति को कवर किया, लेकिन वास्तविक नुकसान (30%) बीमाकृत नहीं था।

Number of Events Above \$1B

2023 Natural Disaster Events and Loss Trends



बीमाकर्ताओं के निहितार्थ:

- न्यूजीलैंड, इटली, ग्रीस, स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे यूरोपीय देशों को रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक मौसम संबंधी बीमात जोखिमों का सामना करना पड़ा।

Face to Face Centres





7 February, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ)



हाल ही में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि नवगठित अनुसंधान बोर्ड, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रावधान लागू हो गए हैं।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन(एनआरएफ):

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन(एनआरएफ) एक नवगठित अनुसंधान निधि संगठन है।
- एनआरएफ अधिनियम 2023 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसके प्रावधान 5 फरवरी, 2024 को लागू हुए।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस में अनुसंधान का समर्थन करना है।
- इसका प्रारंभिक कोष ₹50,000 करोड़ है, जिसमें लगभग ₹36,000 करोड़ निजी क्षेत्र से आने का अनुमान है और इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- इसमें 2008 में स्थापित मौजूदा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को शामिल किया गया है, जिसका विस्तारित अधिदेश एसईआरबी से परे गतिविधियों को कवर करता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर को निकाय का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है।

धन्यवाद प्रस्ताव



हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दिया।
धन्यवाद प्रस्ताव:

- धन्यवाद प्रस्ताव भारतीय संसद में एक प्रस्ताव है जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का प्रावधान करता है।
- अभिभाषण में राष्ट्रपति पिछले और अगले वर्षों के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हैं।
- यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल के एक सांसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है।

ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल



हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) जैव विविधता मानक ने जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कारकों और स्वदेशी लोगों पर उनके प्रभाव की रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया है।
वैश्विक रिपोर्टिंग पहल के बारे में:

- ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र मानक संगठन है जो संगठनों को उनके पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक और शासन प्रदर्शन पर रिपोर्ट करने में मदद करता है।
- इसकी शुरुआत 1997 में सेस और टेलस इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) से समर्थन प्राप्त करके की गई थी।
- 1999 में स्थापित, जीआरआई की स्वैच्छिक स्थिरता रिपोर्टिंग रूपरेखा का उपयोग 100 से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों, एसएमई, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग समूहों द्वारा किया जाता है।
- यह कंपनियों और संगठनों को उनके प्रदर्शन पर रिपोर्ट करने में मदद करने के लिए निःशुल्क स्थिरता रिपोर्टिंग दिशानिर्देश तैयार करता है।
- इसके नए मानकों का उद्देश्य व्यवसायों, सरकारों और अन्य संस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार पर उनके प्रभावों को समझने और रिपोर्ट करने में मदद करना है।
- इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है।

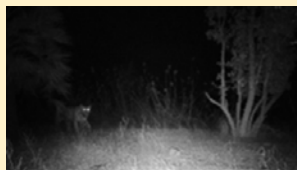
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान



हाल ही में, बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क (बीएनपी) में छह-लेन एलिफेंटेड राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पार्क पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया है।
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, कर्नाटक के दक्षिण में अनेकल पर्वत श्रृंखला (Anekal range of mountains) की पहाड़ियों में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- स्वर्णमुखी नदी की धारा पार्क में जानवरों के लिए प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करती है यह इसके केंद्र से होकर बहती है।
- 2002 में, पार्क का एक हिस्सा बन्नेरघट्टा जैविक पार्क बन गया, जो भारत में बाढ़ से घिरे हाथी अभयारण्य वाला पहला जैविक पार्क था।
- **वनस्पति:** पार्क में नार्सिसस लैटिफोलिया, श्रुचिआ ओलेओसा, चंदन, इमली, नीलगिरी आदि सहित विविध वनस्पतियां हैं।
- **जीव-जंतु:** पार्क विभिन्न प्रजातियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है, जिनमें लुप्तप्राय एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीव जैसे सांभर हिरण, स्लॉथ भालू और पैंगोलिन शामिल हैं।

पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान



हाल ही में, एक अकेला नर बाघ एलुरु जिले के अंत से अच्छे स्वास्थ्य के साथ पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान (पीएनपी) के अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गया है।
पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान (पीएनपी) आंध्र प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है।
- इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह 1,012.86 वर्ग किलोमीटर (391.07 वर्ग मील) में विस्तारित है।
- यह पार्क पूर्वी घाट की पापिकोंडालु पहाड़ियों में, गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर स्थित है।
- ऐतिहासिक रूप से, यह 1882 में एक आरक्षित वन से 1978 में एक वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित हो गया और अंततः 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया।
- 2016 में, आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान तीन बाघों को वहां देखा गया था।
- इसके परिदृश्य को दो बाघ गणनाओं - 2018 और 2022 में शामिल किया गया था।
- यह उद्यान मुख्य रूप से नम पर्णपाती वन से आच्छादित है और बाघ, हिरण और गौर सहित विभिन्न जानवरों का आवास है।

Face to Face Centres





7 February, 2024

एमक्यू-9बी ड्रोन 	हाल ही में, अमेरिका ने खुलासा किया है कि वह भारत को लगभग 4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 सशस्त्र ड्रोन (MQ-9B) की आपूर्ति करेगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय जागरूकता क्षमता में वृद्धि होगी और उसे इन विमानों का पूर्ण स्वामित्व भी मिल जाएगा। MQ-9B ड्रोन के बारे में : - MQ-9B ड्रोन, जिसे प्रीडेटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, एक मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है जिसके दो प्रकार हैं: स्काईगार्डियन और सीगार्डियन। - इसकी पेलोड क्षमता 3,850-पाउंड (1,746 किलोग्राम) है। - इसमें नौ हार्डवेयर हैं जो सेंसर, लेजर-निर्देशित बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकते हैं। - भारतीय नौसेना 2020 से MQ-9B के सीगार्डियन संस्करण का संचालन कर रही है। - सीगार्डियन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर सकता है और 2,721 किलोग्राम की ईंधन क्षमता के साथ 5,670 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है।
विंडस्क्रीन धुंध 	धुंध के बारे में: - बारिश के दौरान वाहन की विंडस्क्रीन पर धुंध पानी की छोटी-छोटी बूंदों के प्रकाश बिखरने के कारण होती है जिससे शीशा अपारदर्शी हो जाता है। - डिटर्जेंट में भिगोए कपड़े से विंडस्क्रीन को पोंछने से कांच पर अवशेष रह जाता है जिससे पानी की बूंदों का सतही तनाव कम हो जाता है। - सतह का तनाव कम होने से पानी की बूंदें फैलने लगती हैं। - सूखे बाथरूम के दर्पण पर साबुन से लिखने के समान डिटर्जेंट द्वारा छोड़ा गया अवशेष पानी की बूंदों के व्यवहार को बदलकर धुंध को रोकने में मदद करता है। - जब गर्म स्नान या शॉवर के बाद भाप दर्पण पर संचयित होती है तो साबुन के साथ लिखने वाले क्षेत्र धुंधले नहीं होते हैं जो पृष्ठभूमि की धुंध के विपरीत होता है। - यह घटना डिटर्जेंट से लथपथ कपड़े का उपयोग करके विंडस्क्रीन धुंध को रोकने के लिए एक व्यावहारिक विधि को दर्शाती है जो बारिश के दौरान बंद खिड़कियों के साथ गाड़ी चलाते समय विशेष रूप से उपयोगी है।
सुर्खियों में स्थल जॉर्जिया	हाल ही में, जॉर्जियाई राष्ट्रपति सैलोम ज़ुराबिश्विली ने अलग हुए अब्खाजिया क्षेत्र में एक नौसेना बेस स्थापित करने की रूसी योजना की निंदा की। जॉर्जिया (राजधानी: त्बिलिसी)  अवस्थिति : जॉर्जिया काकेशस क्षेत्र का एक देश है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के मध्य स्थित है। भौगोलिक सीमाएँ: जॉर्जिया अपनी सीमा अज़रबैजान (पूर्व और दक्षिण पूर्व), काला सागर (पश्चिम), रूस (उत्तर और उत्तर पूर्व), तुर्की (दक्षिण पश्चिम) और आर्मेनिया (दक्षिण) के साथ साझा करता है। भौतिक विशेषताएँ: - लिखी रेंज या सुरमी रेंज (Likhi Range or Surami Range) जॉर्जिया में एक पर्वत श्रृंखला है जो देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। - माउंट शेखरा (Mount Shkhara) जॉर्जिया का सबसे ऊँचा पर्वत है और दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत माउंट जंगा है। - रियोनी और मटक्वारी (Rioni and the Mtkvari) जॉर्जिया की प्रमुख नदियाँ हैं।

POINTS TO PONDER

- रोटोरुआ झील किस देश में स्थित है, जहां इसके हाइड्रोथर्मल सिस्टम के बारे में हाल ही में खोज की गई थी? - **न्यूजीलैंड**
- गामा रे एस्ट्रोनामी पीईवी एनर्जी चरण-3 (ग्रेप्स-3) परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? - **कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करना**
- हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रिपोर्ट को मंजूरी दी? - **उत्तराखंड**
- कौन सा यूरोपीय देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया? - **फ्रांस**
- वायु शक्ति 24 अभ्यास कहाँ होने वाला है? - **पोखरण**

Face to Face Centres

